भारतीय अर्थव्यवस्था

क्षेत्र

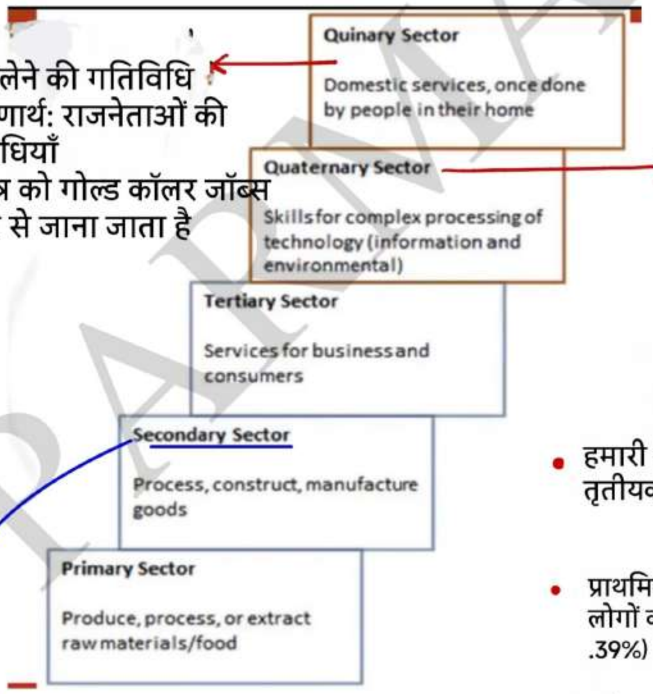

निर्णय लेने की गतिविधि
उदाहरणार्थ: राजनेताओं की गतिविधियाँ
इस क्षेत्र को गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से जाना जाता है

जो वैज्ञानिक अत्यधिक योग्य होते हैं उन्हें ज्ञान क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है

उदाहरण: वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारी

सकल घरेलू उत्पाद: 31.46% में योगदान

- हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान: तृतीयक क्षेत्र (भारत+अन्य देश)
- प्राथमिक क्षेत्र अधिक संख्या में रोजगार देता है। लोगों का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान (14 .39%)
- तृतीयक क्षेत्र में सबसे कम लोग कार्यरत हैं और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान सबसे अधिक है (54.15%)

तृतीय क्षेत्र

- सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है
- यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जहां व्यवसाय सेवाओं का उत्पादन करता है
- गतिविधियाँ - शिक्षण, परिवहन, विज्ञापन, खुदरा
- यह प्रकृति में सदैव अमूर्त है
- व्हाइट-कॉलर नौकरियाँ

द्वितीयक क्षेत्र

- इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है
- ये कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाते हैं
- ब्लू कॉलर नौकरियाँ
- गतिविधियाँ - विनिर्माण, प्रसंस्करण, भवन/निर्माण कार्य
- द्वितीयक क्षेत्र को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है
  किसी देश के औद्योगीकरण में मदद करता है
  उदाहरण: चीन

प्राथमिक क्षेत्र

- सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर
- कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है
- भारत में प्राथमिक क्षेत्र अधिकतर कृषि में देखा जाता है
- रेड-कॉलर नौकरियाँ
- गतिविधियाँ - कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना और एकत्र करना, वानिकी और खनन

समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

- व्यापक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने के लिए सरकार/देशों की कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है
- सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति
- Father - J. M. Keynes (England)

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

- व्यक्तियों/व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है
- व्यक्ति, फर्म
- पिता - एडम स्मिथ (The wealth of Nation)

आर्थिक प्रणालियों के प्रकार

	पूंजीवादी	समाजवादी	मिश्रित
1. स्वामित्व	व्यक्तिगत (US)	सार्वजनिक (रूस) (सरकार)	दोनो (भारत)
2. आर्थिक उद्देश्य/मकसद	लाभ	समाज कल्याण	दोनो
3. सरकार की भूमिका	कोई भूमिका नही	पूरी भूमिका	सीमित भूमिका
4. आय का वितरण	असामान	समान	कम असमान
5. आर्थिक स्वतंत्रता	पूरी स्वतंत्रता जैसे - USA	स्वतंत्रता की कमी जैसे - USSR , North Korea	सीमित स्वतंत्रता जैसे - भारत

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय
- किसी देश के भीतर अर्जित कुल धन
- Intercountry — भारत, अमेरिका, चीन आदि जैसे विभिन्न देशों में विकास
- Intracountry — देश के अंदर पिछले साल की तुलना में कितनी ग्रोथ हुई है
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$

(सूत्र)
- $GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - सकल अप्रत्यक्ष कर
- $GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी
- $GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- GDP – Depreciation = Net DP
- GDP + NFIA = Gross NP
- घरेलू आय जीडीपी के अंतर्गत नहीं आता हैं।

NNP_{FC} :को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता हैं।

- **Market Price** → बाजार मूल्य बेचे जा रहे उत्पाद का अंतिम मूल्य है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।
- **Factor Cost** → फैक्टर लागत उत्पादन के कारकों की लागत,या इनपुट का कुल मूल्य है, जहां अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है

- हरित GDP = GDP – पर्यावरण क्षति
- संभावित GDP – Real GDP = मंदी का अंतर

व्यक्तिगत आय
- किसी व्यक्ति की करों से पहले सभी स्रोतों से अर्जित कुल आय
- व्यक्तिगत आय (PI) = राष्ट्रीय आय + प्राप्त आय अर्जित नहीं - अर्जित आय लेकिन प्राप्त आय
- व्यक्तिगत आय (PI) = राष्ट्रीय आय + स्थानांतरण भुगतान - अवितरित कॉर्पोरेट लाभ
  - ↓ उदाहरण: सरकार द्वारा सब्सिडी।
- उदाहरण: सरकार द्वारा सब्सिडी।
- व्यक्तिगत डिस्पोजल आय : व्यक्तिगत आय – कर

क्रय शक्ति समता (PPP)
- सामान की एक सामान्य टोकरी
- भारत की → सकल घरेलू उत्पाद: दुनिया में 5वें स्थान पर
- ↓ PPP: संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा
  - ↓ अर्थव्यवस्था चरमरा गई है

GDP की गणना करने के तरीके
- MOSPI (सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा GDP गणना
- मूल्य वर्धित विधि
  - उत्पादन विधि के रूप में भी जाना जाता है
  - Value added method = Output – Input
- आय विधि
  - कर्मचारियों को मुआवजा
  - परिचालन अधिशेष
  - मिश्रित आय
- व्यय विधि
  - व्यय विधि
  - C + G + I + (X – M)
  - C: Consumption (उपभोग)
  - G: Govt. expenditure (सरकारी व्यय)
  - I: Investment (निवेश)
  - X: Export (निर्यात)
  - M: Import (आयात)

Measures & Aggregates

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
- सकल घरेलू उत्पाद
- किसी देश के क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य
- 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री "साइमन कुज़नेत्स" द्वारा विकसित किया गया
- सेकेंड हैंड सामान की कभी गिनती नहीं की जाती
- Real GDP vs Nominal GDP
  - → मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक
  - Real GDP:
    - आधार वर्ष को आधार प्रभाव के रूप में जाना जाता है — Base effect
    - स्थिर कीमतों पर गणना
    - यह मुद्रास्फीति समायोजित है
  - Nominal GDP:
    - मौजूदा कीमतों पर गणना
    - मुद्रास्फीति को समायोजित नही किया जाता हैं।
  - इरविन फिशर ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया: धन भ्रम की अवधारणा
  - GDP डिफ्लेटर का उपयोग गणना के लिए किया जाता है।
    - GDP = $\frac{\text{नॉमिनल GDP}}{\text{वास्तविक GDP}} \times 100$

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product)
- देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य
- GNP = GDP – Factor Income to Abroad + FI from Abroad
- GNP = GDP + Net factor income from abroad

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)
- शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product)
- NDP: शुद्ध घरेलू उत्पाद
  - NDP = सकल घरेलू उत्पाद – मूल्यह्रास
  - मूल्यह्रास ↓ किसी परिसंपत्ति का मौद्रिक मूल्य समय के साथ विभिन्न कारणों से घटता जाता है
- वित्तीय वर्ष — 1 अप्रैल to 31st मार्च

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)
- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Products)
- NNP: शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
  - NNP = सकल राष्ट्रीय उत्पाद - मूल्यह्रास

PARMAR SSC

बजट और कराधान

बजट
- एक निर्दिष्ट अवधि में राजस्व और व्यय का अनुमान
- वार्षिक राजकोषीय विवरण (अनुच्छेद 112)
- द्वारा तैयार – आर्थिक मामलों का विभाग (वित्त मंत्रालय)
- द्वारा प्रस्तुत – वित्त मंत्री
- द्वारा प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया – आर. के. शनमुखम चेट्टी
- द्वारा दूसरा बजट – जॉन मथाई समिति
- सबसे अधिक बजट
  - मोरारजी देसाई (10 बार)
  - पी चिदम्बरम (9 बार)।
  - प्रणब मुखर्जी (8 बार)
- प्राप्ति > व्यय – अधिशेष बजट।
- व्यय > प्राप्ति – घाटे का बजट
- व्यय = प्राप्ति – संतुलित बजट

##
- संपत्ति (Asset)
  - किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति (कुछ ऐसा जो किफायती मूल्य का हो)
  - जैसे: सोना, संपत्ति
- देयता (Liability)
  - कुछ ऐसा जिसके लिए कोई जिम्मेदार है (ऋण/दायित्व)
  - जैसे: ऋण का भुगतान

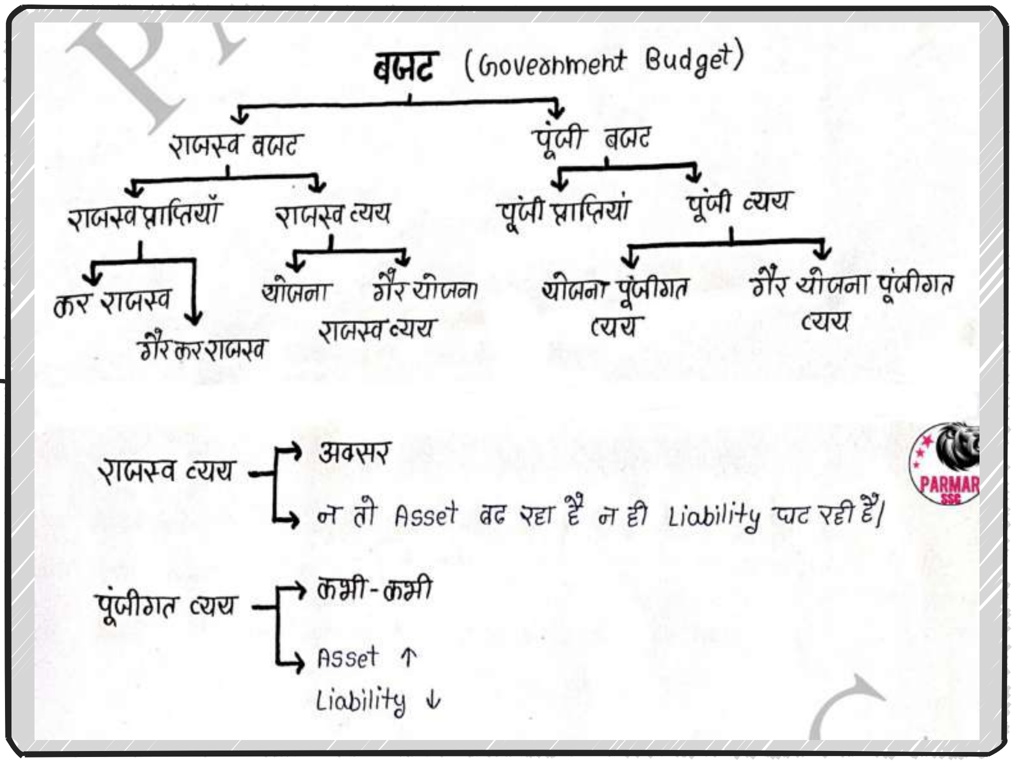

- अधिभार कर – टैक्स पे टैक्स (अमीर लोगों पर)
- उपकर कर/सेस(Cess Tax) – एक निश्चित उद्देश्य के लिए (सभी पर लगाया गया)
- पिगौवियन कर (Pigouvian Tax) – नकारात्मक बाह्यताओं को कम करना

वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- 101 संविधान संशोधन
- परिचालन: 1 जुलाई 2017
- असम इसका अनुमोदन करने वाला पहला राज्य था
- GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है: अनुच्छेद 279 A
- 33 सदस्य (केंद्र से 2+राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 31)
- अध्यक्ष: वित्त मंत्री

कराधान प्रणाली
- प्रत्यक्ष कर
  - सीधे सरकार को देय।
  - इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता
  - बढ़ा हुआ कर
  - जैसे: आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर
  - कॉरपोरेट कर
- अप्रत्यक्ष कर
  - अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को देय।
  - इसे किसी और को दिया जा सकता है
  - प्रतिगामी कर
  - जैसे: जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क

घाटा (Deficits)
- बजटीय घाटा
- राजस्व घाटा – राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्ति
- राजकोषीय घाटा
  - सरकार का सटीक माप। घाटा/सरकारी उधार
  - कुल व्यय = [कुल रसीद - पूंजीगत रसीद बनाने वाला विभाग]
  - कुल व्यय = [राजस्व प्राप्ति + गैर-ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्ति]
- प्राथमिक घाटा – राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
- प्रभावी राजस्व घाटा – राजस्व घाटा -विकास संबंधी दिया गया अनुदान

बजट के घटक
- राजस्व व्यय
  - वेतन/पेंशन
  - सब्सिडी/अनुदान
  - ब्याज भुगतान
  - बुनियादी ढांचे का रखरखाव
- पूंजीगत व्यय
  - किसी भी बुनियादी ढांचे का निर्माण
  - भूमि/मशीनरी की खरीद
  - निवेश
  - ऋण
  - ऋण का पुनर्भुगतान

मांग एवं आपूर्ति

PARMAR SSC

माँग (Demand)
- संतुष्टि - उपयोगिता
- सामर्थ्य
- कुछ खरीदने की उत्सुकता

सीमांत उपयोगिता (Marginal Utility)
- वह अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ जो उपभोक्ता को किसी वस्तु/ सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से प्राप्त होता है

मांग वक्र
- उपभोक्ता पक्ष - सामर्थ्य

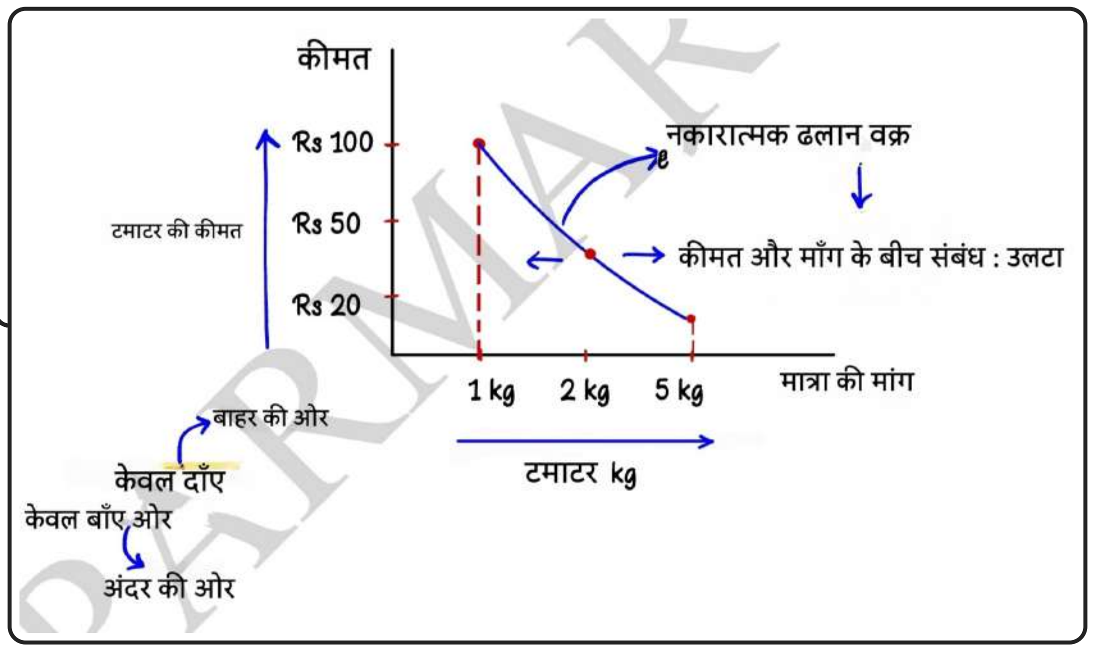

आपूर्ति वक्र
- उत्पादक की ओर से/लाभप्रदता

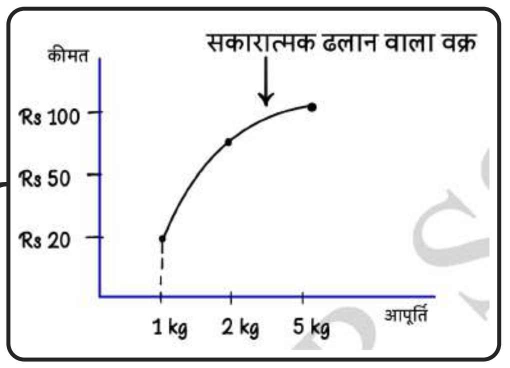

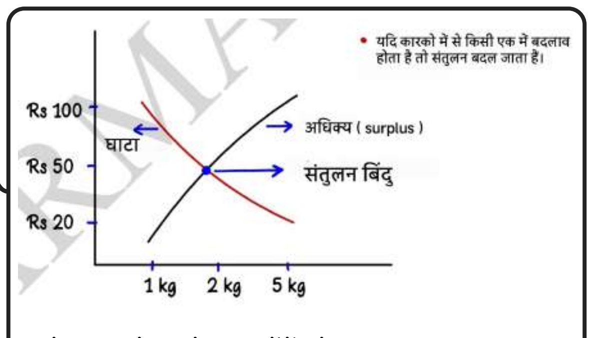

Things exists in equilibrium

अपवाद
- गिफ़ेन वस्तु (Giffen goods)
  - गैर-लक्जरी सामान
  - उदाहरण - गेहूँ के मूल्य में वृद्धि
- वेब्लेन वस्तु
  - लक्जरी वस्तुओं
  - मांग पूर्णतया बेलोचदार है
  - उदाहरण के लिए: आईफोन, मर्सिडीज

मूल्य लोच
- कीमत में परिवर्तन (आमतौर पर -ve) मांग में परिवर्तन को प्रभावित करता है
- $e_d = \frac{\%\ change\ in\ demand}{\%\ change\ in\ price}$
- पूर्णतया लोचदार माँग (Perfectly Elastic Demand)

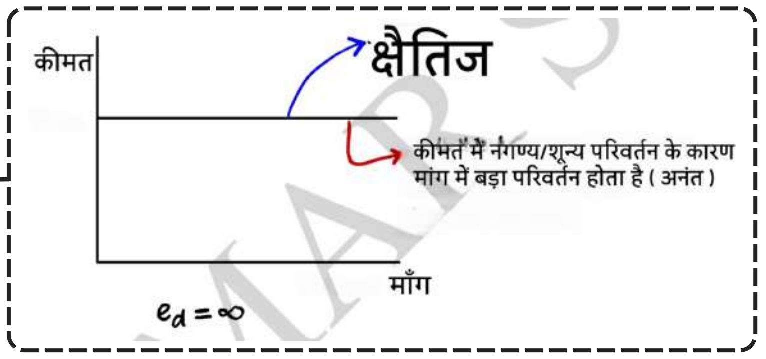

- सापेक्षतः लोचदार माँग (Relatively Elastic Demand)

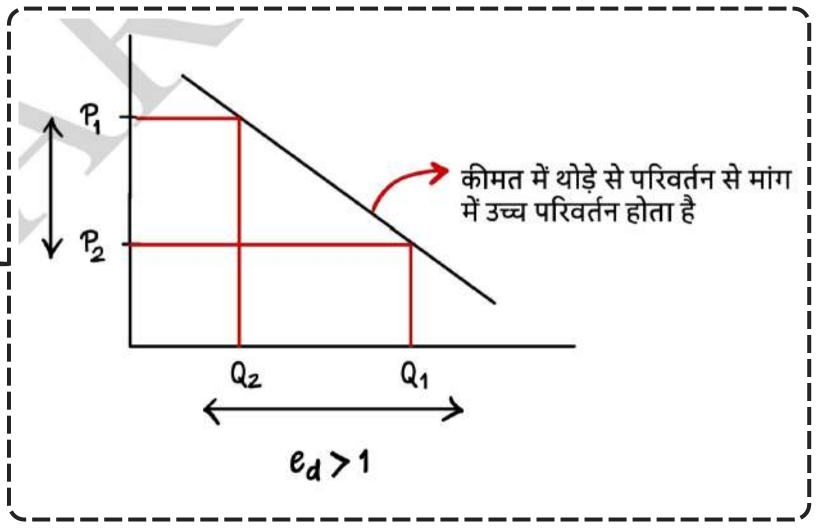

लोग तीन उद्देश्यों के लिए पैसा रखते हैं
- लेन-देन का उद्देश्य
- एहतियाती उद्देश्य
  - भविष्य
  - प्राप्ति व्यय
- अव्यवहार्य उद्देश्य (Speculative motive)
  - जे एम कीन्स (अर्थशास्त्र के जनक) द्वारा
  - आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक - एडम स्मिथ

बाज़ार के प्रकार
- एकाधिकार (Monopoly)
  - केवल । विक्रेता
  - शुद्ध एकाधिकार दुर्लभ है
  - प्रवेश अवरोधक
  - उदाहरण: भारतीय रेलवे
- अल्पाधिकार (Oligopoly)
  - कुछ प्रमुख विक्रेता
  - बहुत सारे खरीददार
  - आसान प्रवेश नहीं
  - जैसे: टेलीकॉम सेक्टर, लैपटॉप मार्केट
- एकाधिकार बाजार (Monopolistic Competition)
  - अनेक विक्रेता
  - बहुत सारे खरीददार
  - समान लेकिन थोड़े अलग उत्पाद
  - जैसे: टूथपेस्ट
- पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition)
  - अनेक विक्रेता
  - बहुत सारे खरीददार
  - (सजातीय उत्पाद बेचना)
  - नि:शुल्क प्रवेश एवं निकास
  - उदाहरणार्थ: कृषि उत्पाद

मूल्य लोच
- पूर्णतया बेलोचदार मांग Perfectly Inelastic Demand

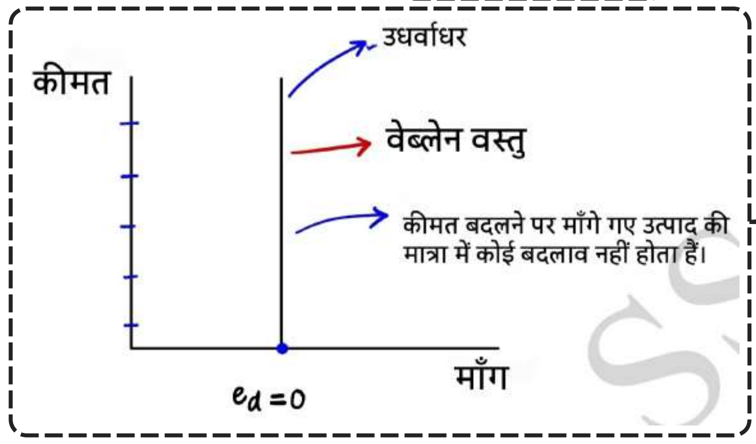

- सापेक्षतः बेलोचदार माँग (Relatively Inelastic Demand)

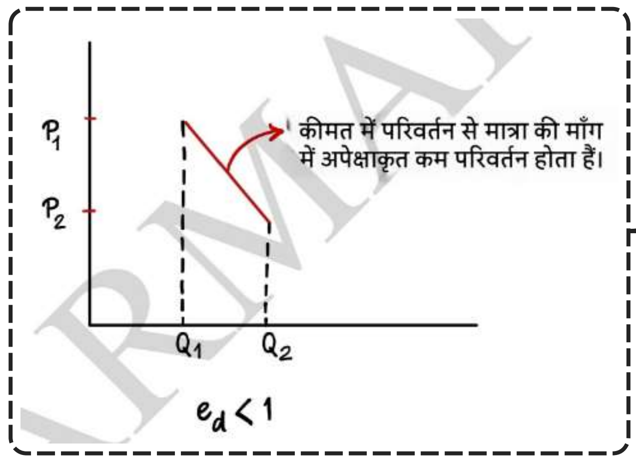

- आय लोच
  - आय में परिवर्तन और कुछ वस्तुओं की मांग के बीच संबंध
  - Income↑ Demand↑ +ve slope
  - Income↓ Demand↓ +ve slope
- आड़ी/ तिरछी मूल्य लोच

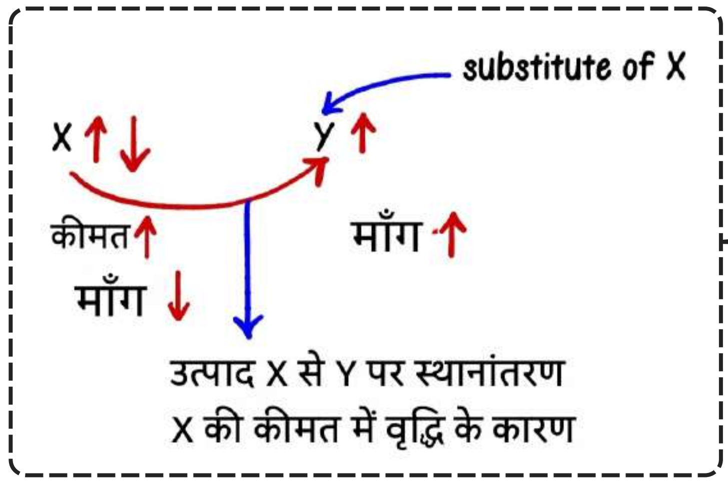

महँगाई और बेरोज़गारी

मुद्रास्फीति
- वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि
- मुद्रास्फीति की स्थिति में क्रय शक्ति कम हो जाती है
- इरविन फिशर
  - मौद्रिक भ्रम की अवधारणा
  - MV = PT
- मुद्रास्फीति के दौरान कर्ज़दार/उधारकर्ता को ऋणदाता से अधिक लाभ होता है

मुद्रास्फीति के कारण
- मांग जनित
  - मांग जनित मुद्रास्फीति
  - "बहुत कम वस्तुओं के पीछे बहुत अधिक डॉलर"
- लागत जनित
  - लागत जनित मुद्रास्फीति
  - उत्पादन और इनपुट लागत के किसी भी कारक की लागत में वृद्धि

मुद्रास्फीति का मापन
- WPI
  - थोक मूल्य सूचकांक
  - विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व
  - सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है
  - आधार वर्ष - 2011-12
  - द्वारा प्रकाशित: आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- CPI
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
  - खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व
  - उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से जाँच की जाती हैं।
  - आधार वर्ष 2011-12
  - द्वारा प्रकाशित: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
  - मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए RBI CPI (संयुक्त) का उपयोग करता है

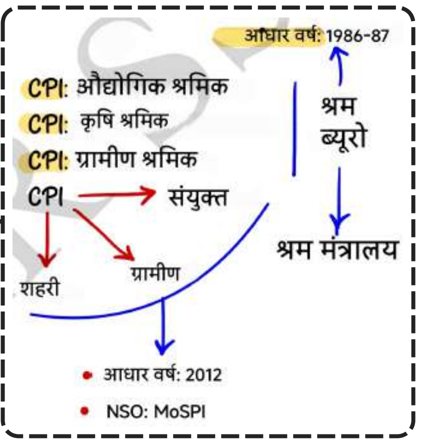

मुद्रास्फीति के प्रकार
- रेंगती हुई मुद्रास्फीति (Creeping) — 3-4%
- चलना (Walking) — 4-10%
- दौड़ना (Running) — 10-20%
- कूदती हुई मुद्रास्फीति (Galloping) — 20-100%
- अति मुद्रास्फीति (Hyperinflation) — 100%

अवस्फीति (Disinflation)
- महंगाई की दर कम होती हैं।

अपस्फीति (Deflation)
- अवस्फीति के विपरीत
- कीमतों के सामान्य स्तर में गिरावट
- क्रय शक्ति बढ़ती है

बेरोजगारी के प्रकार
- संरचनात्मक बेरोजगारी
  - कौशल और नौकरी की आवश्यकताओ का बेमेल (शहरी क्षेत्र मे)
  - उदाहरण के लिए: प्रौद्योगिकी उन्नति, जैसे किसान श्रम की जगह मशीनरी लेना
- शिक्षित बेरोजगारी
  - डिग्री बेरोजगारी (भारत के शहरी क्षेत्र में)
- Frictional unemployment
  - नई नौकरी की तलाश करते समय बेरोजगारी का प्रकार
  - उदाहरण के लिए: एक कर्मचारी किसी बेहतर नौकरी पर जाने के लिए वर्तमान नौकरी छोड़ रहा है (शहरो में देखा जाता है)
- प्रच्छन्न बेरोजगारी
  - जब कुछ लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, लेकिन नहीं हैं, तो सीमांत उत्पादकता शून्य होती है
  - जैसे: कृषि क्षेत्र
- चक्रीय बेरोजगारी
  - अर्थव्यवस्था में मंदी (उतार-चढ़ाव)
  - जब अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती है, तो रोजगार का अवसर मिलता है, जैसा कि शहरी क्षेत्र में देखा जाता है
  - उदाहरणार्थ: महान मंदी
- मौसमी बेरोजगारी
  - मौसमी आधार पर रोजगार
  - भारत के ग्रामीण भाग में अधिक देखा जाता है
  - उदाहरण के लिए: दिवाली के दौरान रोशनी या आतिशबाजी बेचने वाले

मुद्रास्फीतिजनित मंदी
- मुद्रास्फीति (inc.) और बेरोजगारी (inc.)
- कोई आर्थिक गतिविधि नहीं
- महामंदी - 1929-1939
- महान मंदी - 2007-2009

फिलिप्स वक्र
- मुद्रास्फीति (inc.) और बेरोजगारी (dec.) में विपरीत संबंध है

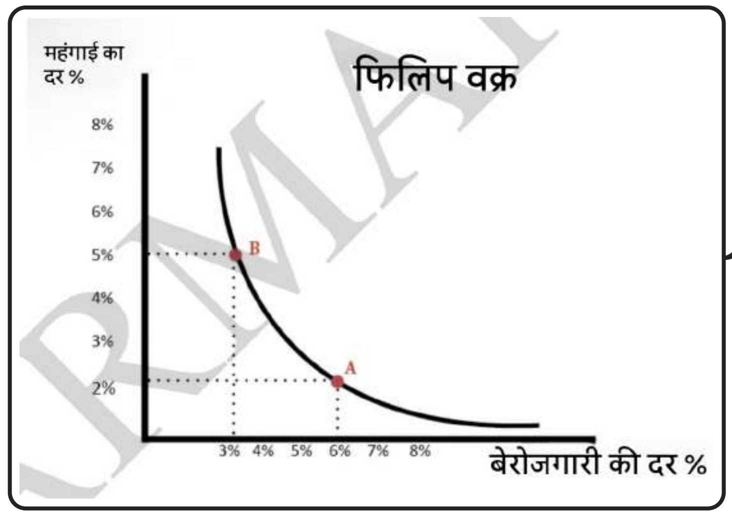

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP - Index of Industrial Production)
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production)
- आधार वर्ष: 2011-12
- द्वारा प्रकाशित - NSO (MoSP)
- 8 प्रमुख उद्योगों का 40% योगदान है
  - रिफाइनरी उत्पाद
  - बिजली
  - इस्पात
  - कच्चा तेल
  - प्राकृतिक गैस
  - सीमेंट
  - उर्वरक
  - कच्चा तेल

मनी और बैंकिंग

PARMAR SSC

NBFC-MFI
- सूक्ष्म ऋण/सूक्ष्म वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है
- माइक्रो फाइनेंस ऋण की न्यूनतम आवश्यकता: कुल संपत्ति का 75%
- स्थापित - एक समिति की सिफ़ारिश के माध्यम से: मालेगाम समिति, 2010 (MFI के मुद्दों को भी देखती है)
- NBFC MFI लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उनके पास माइक्रोफाइनेंस में कम से कम 75% संपत्ति होनी चाहिए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (NBFC)
- उदाहरण: बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा
- वे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत हैं
- सोने पर ऋण और अग्रिम देता है
- वे डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते
- जमा की गारंटी नहीं
- इन्हें RBI द्वारा विनियमित किया जाता है
- उन्हें CRR और SLR बनाए रखने की जरूरत नहीं है

मुद्रा (MUDRA) योजना
- सूक्ष्म वित्त, संपार्श्विक मुक्त ऋण
- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, 2015 में लॉन्च की गई
- 3 प्रकार का ऋण
  - शिशु - 50,000 तक का ऋण
  - किशोर - 50,000-5 लाख तक का लोन
  - तरूण - 5 लाख-10 लाख तक का लोन

सूक्ष्म वित्त संस्थान
- वे कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं
- जैसे: ऋण, बचत, बीमा
- माइक्रोफाइनेंस ऋण 1.25 लाख प्रति वर्ष रुपये से कम आय वाले परिवारों को दिया जाता है।
- सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जनक - मुहम्मद यूनुस (बांग्लादेश)
  - 1970 में ग्रामीण मॉडल बैंक की अवधारणा दी और नोबेल पुरस्कार दिया गया
- भारत में प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान - सेवा (SEWA) बैंक (1974)
- व्यापार मॉडल
  - स्वयं सहायता समूह (SHG)
    - 10-20 लोगों का समूह अपने रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं
    - गरीबी रेखा से नीचे का समूह (बीपीएल) (BPL)
    - आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में
  - संयुक्त दायित्व समूह
    - 4-10 लोगों का समूह
    - लाभ के लिए कोई छोटा व्यवसाय उद्यम हो सकता है
  - अनौपचारिक समूह

आरबीआई के कार्य
- यह बैंकों को नियंत्रित करता है
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
  - लाइसेंस
  - CRR/SLR
  - प्रतिबंध को विनियमित करता है
- मुद्रा मुद्रण
  - Rs. 1 को छोड़कर (वित्त मंत्रालय के अधीन)
  - कानूनी निविदा - फिएट मनी (FIAT Money)
  - प्लास्टिक मनी - क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आदि।
  - हॉट मनी - संपत्तियां जैसे स्टॉक, जमा, बांड आदि

मुद्रा मुद्रण	सिक्का → GOI - ₹1 note
नासिक	मुंबई
देवास	हैदराबाद
मैसूर	कलकत्ता
सालबोनी	नोएडा

- मौद्रिक नीति
- अंतिम उपाय का ऋणदाता और बैंकों का बैंक

1934 का आरबीआई अधिनियम
- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई थी
- हिल्टन यंग कमीशन, 1926 की सिफ़ारिश पर
- 1 अप्रैल 1935
  - आरबीआई मुख्यालय का पहला सेटअप कलकत्ता, वर्तमान में
- 1937 में मुख्यालय मुंबई
- प्रथम आरबीआई गवर्नर - ओसबोर्न स्मिथ
- प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर - सीडी देशमुख
- 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया

बैंकिंग प्रणाली का वर्गीकरण

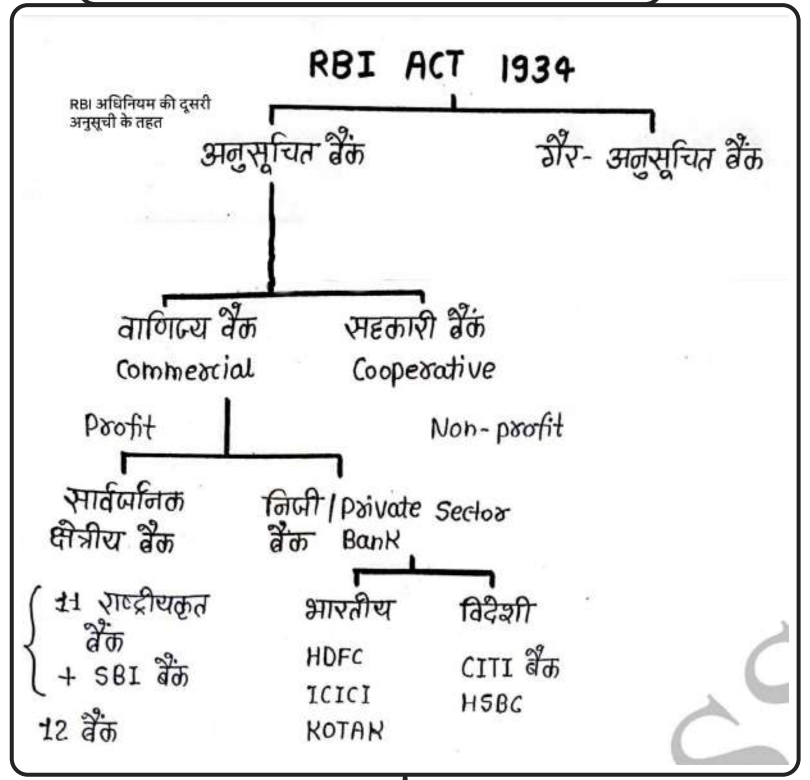

NABARD
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
- बी शिवरामन समिति (1979) की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया
- नाबार्ड अधिनियम 1981 के माध्यम से
- मुख्यालय - मुंबई
- कार्य
  - कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है
  - सहकारी बैंकों और आरआरबी का पर्यवेक्षण करता है
    - रेगुलेट - RBI
    - पर्यवेक्षण - नाबार्ड
  - लोगों से सीधे तौर पर व्यवहार नहीं करता
  - PMAY, KCC, Ru Pay किसान कार्ड के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान करता है

अन्य वित्तीय संस्थान
- राष्ट्रीय आवास बैंक
  - 1988, 1987 के अधिनियम के माध्यम से
- SEBI
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
  - 12 अप्रैल 1988 को स्थापित सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से
  - सांविधिक निकाय
  - मुख्यालय - मुंबई
  - कार्य
    - निवेशकों के हितों की रक्षा करना
  - अध्यक्ष - माधवी पुरी बुच (प्रथम महिला, प्रथम गैर IAS अध्यक्ष)
- IRDAI
  - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
  - स्था. 1999 के आईआरडीएआई अधिनियम के माध्यम से
  - अप्रैल 2000 को एक वैधानिक निकाय के रूप में

बैंकिंग का इतिहास
- प्रथम बैंक - 1770 (बैंक ऑफ हिंदुस्तान)
- 1806 इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता
- 1840 - इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे
- 1843 - इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास
  - विलय
  - 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
  - 1985 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- प्रथम भारतीय स्वामित्व वाला बैंक - इलाहाबाद बैंक, 1865 में
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
  - आरआरबी अधिनियम 1976
  - ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय गतिविधियों को बढ़ाना
  - उदाहरण: ग्रामीण बैंक
  - पहली - प्रथम ग्रामीण बैंक (2 अक्टूबर 1975, मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश)
  - RRB → 50% हिस्सेदारी- केंद्र
    - → 15% " राज्य
    - → 35% " स्पॉन्सर बैंक
- सिडबी (SIDBI)
  - 2 अप्रैल 1990
  - मुख्यालय: लखनऊ

मौद्रिक नीति

राजकोषीय नीति

- राजकोषीय नीति
  - मुद्रास्फीति या अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है
    - कर ↑ → कम डिस्पोजेबल आय
    - सब्सिडी ↓
    - MSP ↑

शुद्ध मांग और समय देयता (NDTL)

- शुद्ध मांग और समय देयता (NDTL) (RBI आपके NDTL का एक हिस्सा रिजर्व के रूप में रखता है)
- Reserve
  - नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)
    - नकदी के रूप में रिजर्व
    - बैंक CRR पर कोई ब्याज दर नहीं कमाते हैं
  - वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquid Ratio)
    - नकद, सोना, जी-सेक के रूप में रिजर्व
    - SLR पर बैंक ब्याज दर कमाते हैं, मुनाफा मिलता है

बैलेंस शीट

Different Assets and Liabilities of a Commercial Bank

	BALANCE SHEET				
	LIABILITIES	AMT	ASSETS	AMT	
Initial Money Invested ←	Share Capital		Vault Cash		→ Cash kept in Bank for Withdrawal by customers
Sometimes bank borrows money from RBI ←	Loan taken from Central Bank if any		Deposits with Central Bank		→ Amount deposited by Bank with RBI
Saving Account, Current Account ←	Demand Deposits		Loans		→ Loan Given to Public
Fixed Deposits/ Recurring Deposits ←	Term Deposits		Investment in Government Securities		→ Amt invested in Government Bonks

Balance Sheet

- देयता
  - जमा
    - डिमांड डिपॉज़िट्स
      - बचत खाता
      - चालू खाता
    - सावधि/सावधि जमा
      - सावधि जमा (एक निश्चित समय पर परिपक्व होती है)
      - आवर्ती जमा (जैसे: म्यूचुअल फंड में एसआईपी)
- संपत्ति
  - ऋण

मुद्रास्फीति/अपस्फीति के मामले में

- RBI अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है
- मौद्रिक नीति उपकरणों की सहायता से
- मौद्रिक नीति समिति
  - उर्जित पटेल समिति की सिफ़ारिश पर
  - 6 सदस्य
    - 3 RBI
      - RBI गवर्नर
      - डिप्टी गवर्नर
      - कार्यकारिणी (Executive)
    - 3 सरकार

मुद्रा गुणक (Money Multiplier)

- प्रत्येक डॉलर के भंडार के लिए बैंकों द्वारा बनाई गई नई धनराशि की अधिकतम राशि
- $MM\downarrow \propto \frac{1}{CRR\uparrow}$

मौद्रिक नीति उपकरण

मात्रात्मक उपकरण

- बैंक दर
  - आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है (बिना कोई प्रतिभूति रखे)
  - 6.75%
  - RBI — Loan to → Banks → No collateral, For long-term
- खुला बाजार परिचालन
  - सीधी खरीद
  - पुनर्क्रय अनुबंध
    - अल्पावधि के लिए G - sec की बिक्री और खरीद
    - पुनर्क्रय अनुबंध
      - रेपो दर: RBI — Loan to → बैंक, अल्पकालिक संपार्श्विक के लिए
      - रिवर्स रेपो दर: बैंक → RBI; रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के साथ भी मुद्रास्फीति का प्रतिकार करता है।
      - सामूहिक रूप से कहा जाता है: तरलता समायोजन सुविधा
    - रेपो का मतलब पुनर्खरीद दायित्व है
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
  - 2% NDTL एक सीमा है
  - रातोरात ऋण
  - CRR और SLR का रखरखाव नहीं किया जाता है
  - जुर्माना + ऋण
  - SLE कोटा G - sec को गिरवी के रूप में उपयोग कर सकते हैं
  - Tools — CRR, SLR, BR, RR, RRR
  - Case 1: मुद्रास्फीति के दौरान
    - → CRR, SLR, BR, RRR, RR
    - नियामकों में वृद्धि
    - मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए ब्याज दरें ऊंची
    - → संकुचनकारी/तंग/प्रिय/हॉकिश मौद्रिक नीति
  - Case 2: अपस्फीति के दौरान
    - → CRR, SLR, BR, RRR, RR
    - नियामकों में कमी
    - ब्याज दरों में कमी
    - → उदार/आसान/विस्तारवादी मौद्रिक नीति
  - मुद्रा जमा अनुपात = $\frac{\text{जनता द्वारा मुद्रा के रूप में रखा धन}}{\text{बैंक में जमा के रूप में धन}}$

गुणात्मक उपकरण

Rationing of Credit
- Certain amount is fixed for industrial , household and other purposes
- Credit supply for each commercial bank is fixed
- Add text here

Change in marginal requirements
- Margin is increased for unnecessary sectors
- Margin is decreased for necessary sectors
- Add text here

Regulation of consumer credit
- Instalment amount, down payment, loan duration are all fixed in advance
- Used to control inflation in country
- Add text here
- Add text here

Moral suasion
- Credit limit for each sector is imposed by rules and regulations
- Guidelines and regulations are fixed by central bank for speculative purposes
- Add text here

बैंकिंग

SARFAESI अधिनियम, 2002
- Securitisation And Reconstruction of Financial Assets &Enforcement of Security Interest Act
- यह बैंक/किसी भी वित्तीय संस्थान को चूककर्ता उधारकर्ता की संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है
- विलफुल डिफॉल्टर
  - किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से लिये गए कर्ज की राशि (Willful defaulter) को जानबूझकर बैंक को वापिस न करना
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC), 2016
  - दिवालियापन पर मौजूदा कानूनों को समेकित करता है

बैड बैंक
- NPAs खरीदने के लिए वित्तीय इकाई की स्थापना
- NPAs की वसूली
- 2021 बजट
  - 2 बैड बैंक स्थापित किये जायेंगे
  - नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)
  - भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL)

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)
- 90 दिन से अधिक का विलंब

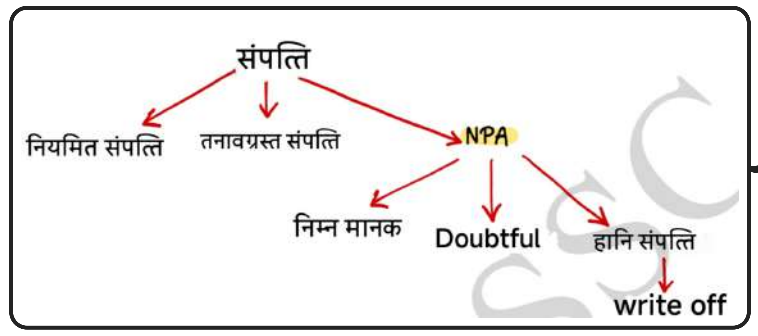

तरलता समायोजन सुविधा LAF
- चलनिधि जाल
  - अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जहां लोग ब्याज दरों में किसी भी बदलाव के बावजूद अपना पैसा रखना पसंद करते हैं जो किसी भी मौद्रिक नीति को अप्रभावी बना देता है
  - कोई खर्च नहीं
  - तब होता है जब दरें बढ़ता है
  - Speculative Demand: पूर्णतया लोचदार
- मुद्रा बाजार
  - अल्पावधि ऋण
  - कॉल मनी
    - एक दिन के अंदर भुगतान करना होगाएक दिन के अंदर भुगतान करना होगा
  - नोटिस मनी
    - 2-14 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है
- पूंजी बाजार
  - दीर्घकालीन ऋण
- ट्रेजरी बिल
  - RBI द्वारा जारी किया जाता है
- बिल की परिपक्वता (Maturity Bills)
  - 1 वर्ष से कम
  - प्रकार
    - 91 दिन
    - 182 दिन
    - 364 दिन
  - हमेशा छूट दर पर सूचीबद्ध होते हैं
  - कोई ब्याज दर नहीं

बेसल मानदंड
- स्विट्जरलैंड में एक जगह है - बेसल
- बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) का मुख्यालय - बेसल, स्विट्जरलैंड
- बेसल समिति, 1974 G10 द्वारा
- 3 मानदंड
  - बेसल I-1988
    - क्रेडिट जोखिम पर ध्यान केंद्रित किया
    - न्यूनतम. जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) पूंजी पर्याप्तता अनुपात के 8% पर पूंजी की आवश्यकता
    - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-एमएफआई (NBFC-MFI)
      - पूंजी पर्याप्तता अनुपात: RWA का 15%
      - NBFC डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता
      - CRR/SLR रखरखाव: नहीं
  - बेसल II 2004
  - बेसल III-2008

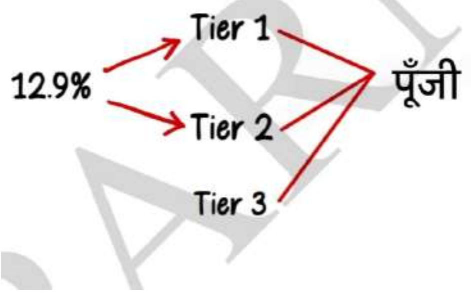

धन के प्रकार
- मुद्रा जो प्रचलन में है
  - जनता के पास मुद्रा
  - बैंक के साथ मुद्रा
- बैंक में जमा
  - डिमांड डिपॉजिट
    - बचत खाता
    - चालू खाता
  - टर्म डिपॉज़िट
    - सावधि जमा
    - आवर्ती जमा
- RBI के पास जमा
  - RBI के पास बैंक जमा
  - RBI के पास अन्य जमा
- डाक जमा
  - डिमांड डिपॉजिट
  - टर्म डिपॉज़िट
  - बैंक के समान

तरलता (Liquidity)
- वह आसानी जिससे किसी परिसंपत्ति या सुरक्षा को उसके बाजार मूल्य को प्रभावित किए बिना तैयार नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है
- डिमांड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट की तुलना में अधिक तरल है
- नकद > चेक > बांड
- प्रत्ययी धन (Fiduciary money)
  - आपसी समझौते
  - जैसे: चेक, बिटकॉइन

मौद्रिक समुच्चय (Monetary Aggregates)
- M0 (घटक)
  - मौद्रिक आधार/उच्च शक्ति वाली मुद्रा/आरक्षित मुद्रा
  - मुद्रा प्रचलन में है
  - बैंकर्स आरबीआई के पास जमा करते हैं
  - आरबीआई के पास अन्य जमाएँ जैसे: सरकारी/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की जमाएँ
- M1
  - जनता के पास मुद्रा
  - डिमांड डिपॉज़िट्स
  - आरबीआई के पास अन्य जमा
- M2
  - M1 + डाकघर के पास बचत जमा
- (M1, M2: संकीर्ण मुद्रा (Narrow Money))
- M3
  - M1 + बैंक के पास सावधि जमा
  - वास्तविक धन आपूर्ति
- M4
  - M3 + डाकघर में सभी जमा
- (M3, M4: ब्रॉड मनी (M3-प्राथमिकता))
- तरलता क्रम - M1 > M2 > M3 > M4

इरविंग फिशर द्वारा

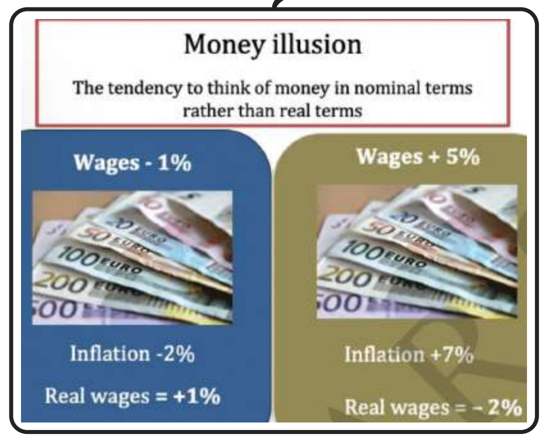

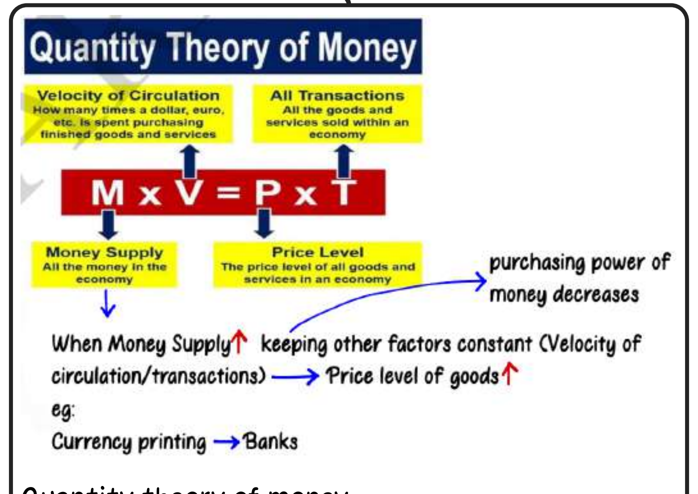

गरीबी

गरीबी
- निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) – बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का गंभीर अभाव
- सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) – घरेलू आय औसत आय से कम है
- व्यक्तिपरक गरीबी (Subjective Poverty)

MPI

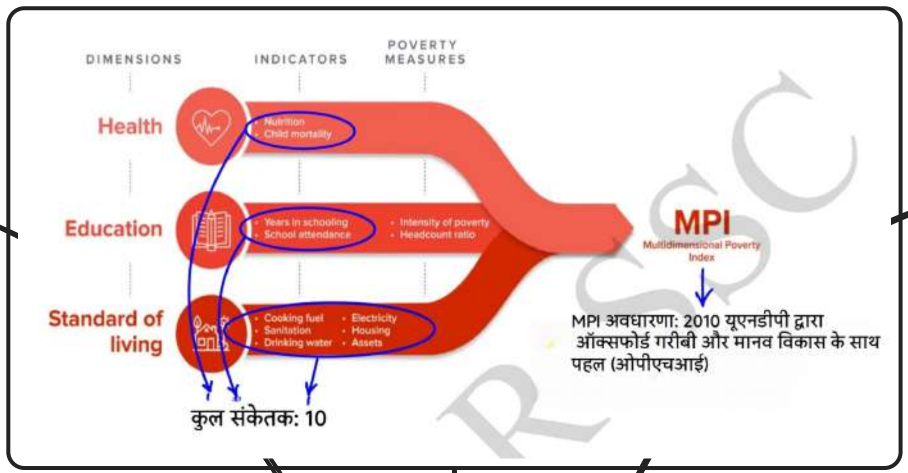

NITI AAYOG
- 12 संकेतक - राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक
- 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी
- 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं
- उत्तर प्रदेश में अधिकतम लोग गरीबी से बाहर निकले हैं

लोरेन्ज़ वक्र
- धन वितरण, आय असमानता की बात करता है
- गिनी गुणांक:- 0 से 1
  - 0 - पूर्ण समानता
  - 1 - पूर्ण असमानता

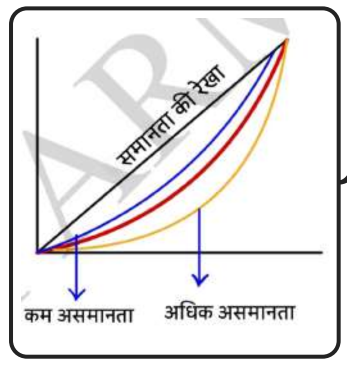

(अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) IMF
- मुख्यालय - वाशिंगटन डी.सी

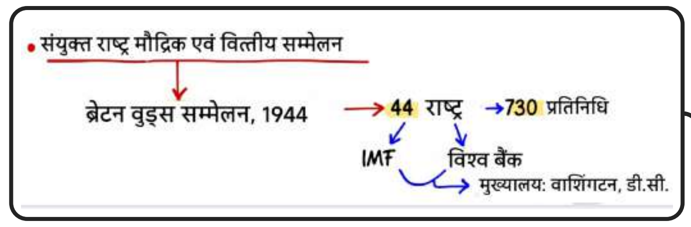

- NOSTRO
  - आपके बैंक में हमारा खाता।
  - उदाहरण: बैंक X का बैंक Y के साथ बैंक Y की घरेलू मुद्रा में एक खाता है
- VOSTRO
  - हमारे बैंक में आपका खाता।
  - उदाहरण के लिए: सिटी बैंक भारत में स्थित एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी करता है और आई-चिह्नित मुद्रा INR के साथ एक खाता खोलता है
- FERA – विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा
  - replaced by
- FEMA – विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
- बाज़ार की शक्तियों के कारण अस्थायी विनिमय दरें
  - मूल्यह्रास (Depreciation)
    - घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी
    - मूल्यह्रास की स्थिति में निर्यातकों को लाभ होगा
  - अधिमूल्यन (Appreciation) – घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि
- सरकारी हस्तक्षेप निश्चित विनिमय दरें
  - अवमूल्यन (Devaluation) – यह आधिकारिक मूल्यह्रास है
  - पुनर्मूल्यन (Revaluation) – यह आधिकारिक पुनर्मूल्यन है

गरीबी का आकलन

आज़ादी से पहले
- सबसे पहले दादाभाई नरोजी ने अपनी पुस्तक - पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से अनौपचारिक गरीबी रेखा दी थी
- He made the earliest estimation of poverty
- राष्ट्रीय योजना समिति, 1938, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, प्रथम अध्यक्ष: जेएल नेहरू
- बॉम्बे प्लान, 1944

आज़ादी के बाद
- दांडेकर और रथ समिति 1971
  - गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया
  - MoSPI के तहत NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) के डेटा का उपयोग किया गया
  - व्यय आधारित गरीबी रेखा
- अलघ समिति 1979
  - पोषण आधारित गरीबी रेखा
  - ग्रामीण 2400 कैलोरी
  - शहरी 2100 कैलोरी
- लकड़ावाला समिति 1993
  - सीपीआई-आईडब्ल्यू (ग्रामीण), सीपीआई-एडब्ल्यू (शहरी) पर आधारित गरीबी रेखा
  - राज्यवार गरीबी रेखा
- तेंदुलकर समिति 2009
  - स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी बुनियादी आवश्यकताओं के अंतर्गत लिया जाना चाहिए
  - क्रय शक्ति समता पर आधारित गरीबी रेखा: यदि कोई प्रतिदिन 33 से अधिक खर्च कर रहा है (गरीब नहीं), तो 33/ दिन से अधिक नहीं (गरीब)
  - समान संदर्भ अवधि को मिश्रित संदर्भ अवधि (स्वास्थ्य/शिक्षा) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
  - गरीबी रेखा (2011-12)
    - ग्रामीण 816/माह
    - शहरी 1000/माह
  - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 21.9% (2011-12)
    - ग्रामीण 25.7%
    - शहरी 13.7%
  - गरीबी अनुपात - 29.5%
    - ग्रामीण 30.9%
    - शहरी 26.4%
  - हेड काउंट अनुपात
    - जनसंख्या का अनुपात BPL
    - $\text{Head count ratio} = \frac{\text{No. of multidimensionally poor people}}{\text{Total Population}}$
- रंगराजन समिति 2014
  - पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत श्रेणियां बनाई गईं
    - कैलोरी
    - प्रोटीन
    - वसा
  - साथ ही संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि के बारे में भी बात की

भुगतान संतुलन संकट
- 1991 - भारत में भुगतान संतुलन संकट
- विदेशी मुद्रा (FOREX) भंडार खाली
  - विदेशी मुद्रा संपत्ति
  - सोने का भंडार
  - विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) (SDR) – मुद्रा - यूएसए, यूरो, येन (जापान) युआन (चीन) और पाउंड (ब्रिटेन)
  - आरक्षित किश्त स्थिति: IMF के भीतर बनाए रखा जाने वाला आवश्यक कोटा
- तत्कालीन पीएम-पी वी नरसिम्हा राव
- तत्कालीन वित्त मंत्री - मनमोहन सिंह

- Debaters in IMF
  - प्रथम - अर्जेंटीना
  - चौथा पाकिस्तान

भुगतान का संतुलन

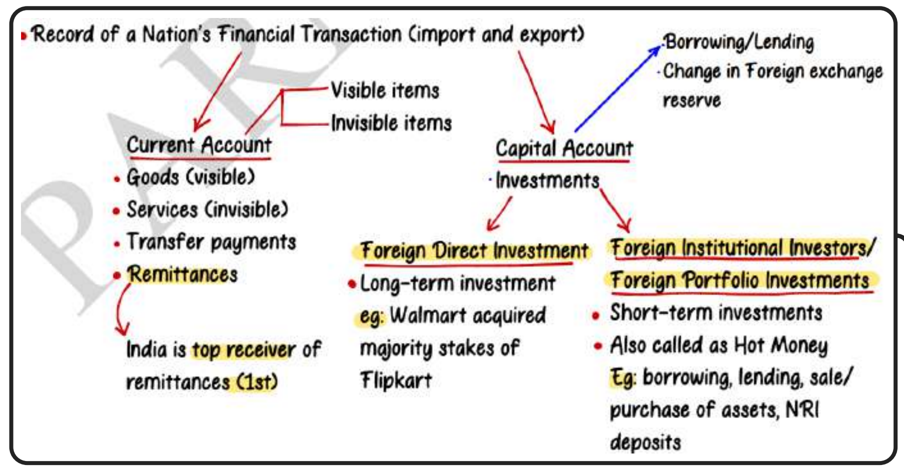

- चालू खाता घाटा (सीएडी) (CAD)
  - सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% (वर्तमान में)
  - आयात का मूल्य > निर्यात का मूल्य
- जुड़वां घाटा = CAD + राजकोषीय घाटा

पंचवर्षीय योजनाएं

योजना आयोग
- अध्यक्ष - PM
- स्वतंत्रता के बाद, 1947
- USSR से लिया गया
- जोसेफ़ स्टालिन द्वारा 1928 में प्रस्तुत किया गया

1st पंचवर्षीय योजना
- 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च किया गया
- हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित
- जवाहरलाल नेहरू के समय
- अवधि – 1951-56
- मुख्य फोकस – प्राइमरी सेक्टर
- लक्ष्य - 2.1 %, उपलब्धि - 3.6% – पूर्णतः सफल
- कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए बांधों का निर्माण
  - भाखड़ा नांगल बांध
  - हीराकुंड बांध
  - नागार्जुन सागर बांध

2nd पंचवर्षीय योजना
- पी.सी. पर आधारित महालनोबिस मॉडल
- जवाहरलाल नेहरू के समय
- अवधि – 1956-61
- मुख्य फोकस – सार्वजनिक क्षेत्र
- लक्ष्य - 4.5%, उपलब्धि - 4.27% – मध्यम रूप से सफल
- तीव्र औद्योगीकरण
  - औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (दूसरा आईपीआर)
  - राउरकेला स्टील प्लांट - ओडिशा (जर्मनी)
  - दुर्गापुर स्टील प्लांट - पश्चिम बंगाल (यूके)
  - भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ (USSR)

3rd पंचवर्षीय योजना
- गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित
- जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समय
- अवधि – 1961-66
- मुख्य फोकस – आत्मनिर्भर एवं स्व-उत्पादक अर्थव्यवस्था
- लक्ष्य - 5.6%, उपलब्धि - 2.8% – असफलता
- युद्ध
  - चीन युद्ध 1962
  - भारत-पाक 1965
- पीएल-480-संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात
- FCI - 14 Jan 1965, CACP - 1 Jan 1965, IDBI - 1 July 1965, UTI - 1963

प्लान हॉलिडे (Plan Holiday)
- 3 साल के लिए – 1966-69
- वार्षिक योजना – नई कृषि रणनीति

4th पंचवर्षीय योजना
- गाडगिल फॉर्मूला/रुद्र एलन मोड पर आधारित
- इंदिरा गांधी के समय
- अवधि – 1969-1974
- मुख्य फोकस
  - स्थिरता के साथ विकास
  - आत्मनिर्भरता की उत्तरोत्तर उपलब्धि
    - परिवार नियोजन
    - 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
    - भूमिगत परमाणु परीक्षण - Smiling Buddha
- लक्ष्य - 5.6%, उपलब्धि -3.3% – एक बड़ी विफलता

5th पंचवर्षीय योजना
- डी.पी. पर आधारित धार मॉडल
- इंदिरा गांधी के समय
- अवधि – 1974-78
- मुख्य फोकस
  - गरीबी हटाओ (गरीबी हटाओ)
  - आत्मनिर्भरता की प्राप्ति
  - न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974)
    - सभी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए
    - 20 अंक कार्यक्रम (1975)
  - आरआरबी (RRB) की स्थापना की गई (1975)
- लक्ष्य - 4.4%, उपलब्धि - 4.8% – थोड़ा सफल

रोलिंग योजना पेश की गई
- जनता सरकार के दौरान/मोरारजी देसाई
- अवधि: 1978-80
- मुख्य फोकस – रोजगार पर जोर दिया गया

6th पंचवर्षीय योजना
- इंदिरा गांधी के समय
- अवधि – 1980-85
- मुख्य फोकस
  - राष्ट्रीय आय
  - प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण
  - बेरोजगारी
  - नाबार्ड की स्थापना की
  - 15 अगस्त 1983 को भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)
- लक्ष्य 5.2%, हासिल किया 5.7% – सफल

7th पंचवर्षीय योजना
- राजीव गांधी के समय
- अवधि – 1985-90
- मुख्य फोकस
  - खाद्यान्न उत्पादन
  - रोजगार के अवसर पैदा हुए
  - उत्पादकता
- लक्ष्य - 5, हासिल किया - 6% – बहुत सफ़ल
- हिंदू विकास दर 1978
  - हिंदू विकास दर 1978
  - 1960-80 तक भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि देखी गई

वार्षिक योजना
- 1990-92

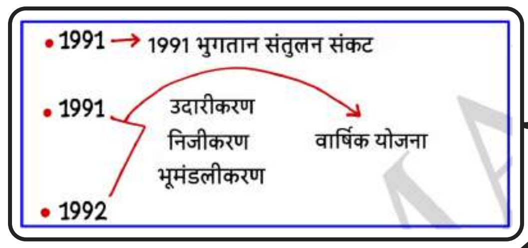

8th पंचवर्षीय योजना
- पी वी नरसिम्हा राव के समय
- अवधि – 1992-97
- मुख्य फोकस
  - नई सांकेतिक नीति
  - आर्थिक और राजकोषीय सुधार
  - सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई (लाइसेंस राज समाप्त हुआ)।
- लक्ष्य - 5.6%, हासिल किया - 6.8% – अत्यधिक सफल

9th पंचवर्षीय योजना
- अटल बिहारी वाजपेई के समय
- अवधि – 1997-2002
- मुख्य फोकस – सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास
- लक्ष्य - 6.5 %, हासिल किया - 5.4%

10th पंचवर्षीय योजना
- अटल बिहारी वाजपेई और मनमोहन सिंह के समय
- अवधि – 2002-2007
- लक्ष्य - 8%, उपलब्धि - 7.6%
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया था

11th पंचवर्षीय योजना
- मनमोहन सिंह के समय
- अवधि – 2007-2012
- मुख्य फोकस – तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर
- लक्ष्य - 9%, हासिल - 8%

12th पंचवर्षीय योजना
- मनमोहन सिंह के समय
- अवधि – 2012-2017
- मुख्य फोकस – तेज़, समावेशी और सतत विकास की ओर

निति आयोग (NITI AAYOG)
- योजना आयोग के स्थान पर
- स्थापित दिनांक: 1 जनवरी 2015
- यह सरकार का एक थिंक टैंक है।
- रिपोर्ट प्रकाशित करता है
- विज़न दस्तावेज़